RAJHIN/2013/57037 Postal Regd. No. : Sriganganagar/252/2020-2022 Posted at Sriganganagar E-mail : sehkargaurav@gmail.com

सहकार गौरव

बैंक, सहकारिता, कृषि, डेयरी, पशुपालन, ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

वर्ष : 9 अंक : 03 पाक्षिक पृष्ठ : 4 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2021 श्रीगंगानगर (राजस्थान) वार्षिक मूल्य : रुपए 250 मोबाइल : 097820-56056

कृषि कानून की वापसी पर संसद की मुहर, अब एमएसपी पर कमेटी बनाने की तैयारी

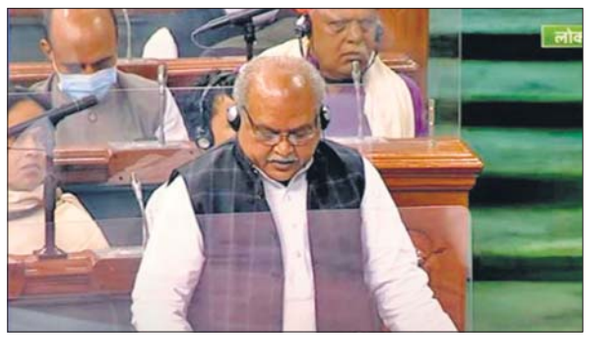

नई दिल्ली। एक साल से दिल्ली की सड़कों सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश में जारी किसान आंदोलन के प्रति केंद्र सरकार के रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सरकार के रुख से प्रतीत होता है कि वो किसान आंदोलन को पूरी तरह खत्म कराने के लिए सक्रिय हो गयी है। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में तीन कृषि सुधार कानून वापस लेने के अगले ही दिन यानी मंगलवार को सरकार ने किसानों की एक और बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कमेटी बनाने की ओर कदम बढा दिया है।

इसके लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी कमेटी बनाने का फैसला लेते हुए कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से 5 किसान नेताओं के नाम सुझाने के लिए कहा है। किसान नेता मनजीत सिंह राय के अनुसार, बुधवार को कमेटी में शामिल होने वालों के नाम की घोषणा की जा सकती है। इससे पूर्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के ठीक 10 दिन बाद, सोमवार को लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। सोमवार को विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच तीन कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। सदन की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही दोपहर दो बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनिमत से उच्च सदन से भी बिल पास हो गया।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीन कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की मांग की। विपक्षी नेताओं के हंगामे के मद्देनजर दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

पीएम ने कानून वापसी का किया था ऐलान

19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का एलान किया था। इसके बाद सरकार ने तेजी से इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी के तहत संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होते ही सरकार ने सबसे पहले इस बिल को लोकसभा से पास कराकर एक कदम आगे बढ़ा लिया है।

सितम्बर 2020 में संसद में पास किये थे कृषि कानून

उल्लेखनीय है कि तीन नए कृषि कानून 17 सितम्बर, 2020 को लोकसभा में पारित किये गये थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 सितम्बर 2020 को कृषि कानून पर हस्ताक्षर किये थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने देश भर में इन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन आरम्भ कर दिया था।

23 सोसाइटी में गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी

जयपुर (सहकार गौरव)। सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में 23 और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए 100-100 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। इसके लिए प्रत्येक समिति को 12 लाख रुपये शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलेंगे।

रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की भुताला, वाटी, कठार और धारोद सोसाइटी में, चूरू जिले की सारायण, तोलासर, भानीपुरा और पुनरास समिति में, बाड़मेर जिले की गुल्ले की बेरी, भागभरे की बेरी, जाखड़ा और रिड़ियातालर समिति में, बांसवाड़ा जिले की आमलीपाड़ा व पिण्डारमा समिति में तथा प्रतापगढ़ जिले (सीसीबी चित्तौड़गढ़) की वीरपुर व बोरदिया सोसाइटी में गोदाम निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गयी है। इसी प्रकार, जिला जोधपुर की कानोड़िया महासिंह, जिला करौली (सीसीबी सवाईमाधोपुर) की मनकपुर, पांचोली व मंडरायल समिति में, जिला झालावाड़ की बोरखेड़ी गुजरान समिति में तथा जिला नागौर की लालावास ग्राम सेवा सहकारी समिति में सौ-सौ मीट्रिक टन गोदाम निर्माण के लिए, प्रत्येक में 12 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

सहकारिता सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ मॉडल : अमित शाह

150 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन, अमूल बना देश का सबसे बड़ा उत्पादक

गांधीनगर। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अमूलफेड डेयरी के आधुनिक सुविधा से युक्त 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट, बटर प्लांट, पैकेजिंग फिल्म प्लांट एवं ऑटोमेटिक रोबोटिक स्टोरेज व रिट्रिवल सिस्टम का उद्घाटन किया। अमूल के संचालन को सुगम बनाने के लिए ऑटोमेटिक रोबोटिक स्टोरेज व रिट्रीवल सिस्टम 23 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकतम तकनीक के साथ शुरू हुआ है। इसके साथ ही अमूल की पैकेजिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रूपए का एक संयंत्र भी यहां लगाया गया है।

इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि अब अमूल देश का सबसे बड़ा मिल्क पाउडर उत्पादक बन चुका है। 85 करोड़ रूपए की लागत से मक्खन के प्लांट का भी आज उद्घाटन हुआ है। शाह ने कहा कि अमूल के सहकारिता आंदोलन का विश्लेषण करने पर इसमें तीन महत्वपूर्ण अंगों का पता चलता है। पहला-दूध का उत्पादन करने वाली गुजरात के 18000 गांवों की हमारी 36 लाख बहनें, दूसरा-इस दूध को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना एवं स्वस्थ तरीके से दूध को अलग-अलग उत्पादों में बदलना, और तीसरा-विपणन। इस प्रक्रिया से उत्पाद सीधे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इन तीनों अंगों को मजबूत करने के कार्यक्रम आज यहां पर शुरू हुए हैं।

भारत के आर्थिक विकास के लिए सहकारिता ही श्रेष्ठ मॉडल

उन्होंने कहा कि इतने विशाल देश और जनसंख्या को सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास से जोड़ना है तो कोई साधारण मॉडल काम में नहीं आ सकता। 130 करोड़ की आबादी को एक साथ रखकर सभी तक विकास को पहुंचाना और विकास की प्रक्रिया में सबको हिस्सेदार बनाना बड़ा कठिन काम है। दुनिया भर में अर्थतंत्र के कई बड़े मॉडल हैं, जो छोटी आबादी के लिए तो ठीक हो सकता हैं लेकिन

भारत ▸▸ शेष @ 3 पर

सहकारिता में अर्थतंत्र को गति देने की क्षमता

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा, 'सहकारिता में न केवल देश के अर्थ तंत्र को नई गति देने की क्षमता है बल्कि देश के सभी लोगों को समृद्ध बनाने का मंत्र भी इसी क्षेत्र का है और अमूल इसका जीता जागता उदाहरण है।

36 लाख बहनें परिश्रम और पारदर्शिता के साथ एक साथ काम करें तो क्या नहीं हो सकता है, इसका उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि कई ऐसी बहनें होंगी जो आज भी पढ़ना लिखना नहीं जानती होगी मगर उनके बैंक अकाउंट के अंदर एक लाख रूपए का चेक जमा होता है और सालाना 75-80 लाख रुपया जमा होता है।'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'सहकारिता का मूलमंत्र यही है कि हो सकता है हमारी क्षमता कम हो सकता है, ज्यादा पढ़े लिखे न हों, हमारे पास ज्यादा पूँजी न हो, मगर हम संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम सब एकत्रित हो जाते हैं तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज जब 36 लाख बहनें एक साथ एकत्रित हो जाती हैं तो अमूल का टर्नओवर 53 हजार करोड़ रुपए का हो जाता है।'

राजस्थान में अलग कृषि बजट पेश होगा, किसानों के साथ सम्भाग स्तरीय सम्वाद आरम्भ

कृषि मंत्री व अधिकारियों ने किया अजमेर सम्भाग के प्रगतिशील किसानों से सम्वाद

जयपुर (सहकार गौरव)। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए एक अभिनव पहल करने जा रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार राजस्थान का कृषि बजट अलग से पेश होगा। इस बजट में खेती, किसानी, पशुपालन, डेयरी और कृषि से जुड़े प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कृषि बजट की पूर्व तैयारी को लेकर गुरूवार को कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया, कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार और आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने अजमेर सम्भाग के प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, सहकारिता व डेयरी विशेषज्ञों तथा विभिन्न विषय विशेषज्ञों से सीधा सम्वाद किया। कृषि मंत्री कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े जबकि शेष सभी

▸▸ शेष @ 3 पर

बीआर एक्ट में संशोधन पर केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस

नई दिल्ली। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर हाल ही में सुनवाई करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका तिरुवल्ला ईस्ट कोऑपरेटिव बैंक और गुरुवायुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ने दायर की थी।

हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि अब शहरी सहकारी बैंकों को प्रबंधन बोर्ड का गठन करने और सीईओ/प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जा

▸▸ शेष @ 3 पर

मंत्रीमंडल में व्यापक फेरबदल, आंजना का सहकारिता मंत्रालय का प्रभार यथावत

जयपुर। राज्य मंत्रीमंडल में व्यापक फेरबदल के बावजूद सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना अपना पद, प्रतिष्ठा व मंत्रालय का प्रभार बरकरार रखने में कामयाब रहे। लम्बे समय से मंत्रीमंडल में विस्तार और फेरबदल की कवायद चल रही थी। करीब 6 माह से मंत्रीमंडल में फेरबदल को लेकर आये दिन एक नया शिगुफा छोड़ा जाता रहा कि कौन रहेगा, कौन जायेगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केवल पांच मंत्रियों के पास ही उनके पुराने विभाग बरकरार रखे, जिनमें उदयलाल आंजना का सहकारिता मंत्रालय का प्रभार भी शामिल हैं। मंत्रीमंडल में फेरबदल के पश्चात सहकारी आंदोलन और सहकारिता सेवा से जुड़े अनेक अधिकारियों, कर्मचारी नेताओं ने आंजना को दूसरी पारी के लिए शुभकामनायें दी।

मंत्रीमंडल में फेरबदल से पूर्व, सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं में

▸▸ शेष @ 3 पर

सीनियर एडिशनल बलाई को मिला एडिशनल वन का अतिरिक्त कार्यभार

जयपुर (सहकार गौरव)। राजस्थान सहकारिता सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दुर्गालाल बलाई को अतिरिक्त रजिस्ट्रार-प्रथम के पद का दायित्व सौंपा गया है। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार श्री बलाई मूलतः अतिरिक्त

▸▸ शेष @ 3 पर

एमडी ने सीयूजी प्लान के साथ 28 माह में डेढ़ लाख रुपये का मोबाइल भत्ता उठाया, जांच में दोषी करार

जयपुर (सहकार गौरव)। सहकारिता विभाग के आदेशों और परिपत्रों को अपनी सुविधा अनुरूप उपयोग करने के लिए चर्चित, सहकारिता सेवा के दागी अधिकारी बजरंग लाल झारोटिया को विभागीय जांच में पद का दुरूपयोग करने और नियमों को ताक में रखे हुए दोहरी मोबाइल सुविधा का उपयोग करने का दोषी पाया गया है। झारोटिया वर्तमान में अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में अधिशासी अधिकारी के पद पर पदस्थापित है और उसकी पोस्टिंग के दिन से ही प्रबंध निदेशक का पद रिक्त होने के कारण, एमडी का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्हीं के पास है।

दागी कार्मिकों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने के कार्मिक विभाग के स्पष्ट निर्देश के बावजूद पांचवीं बार अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में प्रबंध निदेशक का पद हथियाने में सफल रहे उप रजिस्ट्रार कैडर के अधिकारी बजरंग लाल को, इससे पिछले के दो कार्यकाल में इसी बैंक में एमडी रहते हुए दोहरी मोबाइल सुविधा

▸▸ शेष @ 3 पर

पैक्स कर्मचारी संघ भारत में राजावत राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत

देवेन्द्र सैदावत को प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व मिला

जयपुर। राज्य के दो सक्रिय सहकारी नेता राष्ट्रीय मंच से जुड़ गये हैं। दोनों ही नेता राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हैं।

राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सिंह राजावत को पैक्स कर्मचारी संघ भारत का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। वे संघ की जालौर जिला इकाई के अध्यक्ष भी हैं और संघ के

▸▸ शेष @ 3 पर

डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव आईसीए-एपी चेयरमैन निर्वाचित

भारत से आईसीए-एपी के अध्यक्ष बनने वाले पहले सहकारी नेता हैं यादव

नई दिल्ली। भारत के सुप्रसिद्ध सहकारी नेता चंद्रपाल सिंह यादव ने सियोल में मंगलवार को आयोजित आईसीए-एपी के अध्यक्ष पद का चुनाव भारी मतों से जीतकर देश को गौरवान्ति किया है। आईसीए-एपी के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बना है।

इस चुनाव में चंद्रपाल को 185 वोट मिले जबकि जापान से उनकी प्रतिद्वंद्वी चितोस

▸▸ शेष @ 3 पर

अजमेर डेयरी की आमसभा, 900 करोड़ रुपये का बजट पारित, पशुपालकों को मिलेगा 2 साल का बोनस

अजमेर (सहकार गौरव)। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की 30वीं वार्षिक आमसभा 21 नवम्बर को जवाहर रंगमंच पर आयोजित की गई। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी की अध्यक्षता और प्रबंध निदेशक उमेश चंद्र व्यास के सानिध्य में आयोजित आमसभा में समस्त दूध और दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के प्रतिनिधि और गोपालक आम सभा में शामिल हुए। आमसभा की शुरूआत गोपालक भगवान श्रीकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। आम सभा में 550 प्राथमिक दुग्ध समितियों के अध्यक्ष सम्मिलित हुए।

आमसभा को सम्बोधित करते हुए चौधरी ने सर्वप्रथम छठी बार अजमेर डेयरी के संचालन की जिम्मेदारी सौंपने पर पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैंने विगत 30 वर्ष में जिले के दुग्ध उत्पादकों, समितियों एवं जिला दुग्ध संघ के हितार्थ पूरा जीवन कठिन परिश्रम ईमानदारी एवं निःस्वार्थ भावना से सेवा करने का प्रयास किया है। वर्ष 1990 में जब पहली बार अजमेर जिला दुग्ध संघ के संचालक मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, तब एनडीडीबी का लगभग 17 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था, केंद्रीय कृषि मंत्री चौधरी अजीतसिंह के सहयोग से एक मुश्त ऋण समायोजन कर 4 अक्टूबर 2002 को 10 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान कर संघ को ऋण मुक्त किया गया और उसके पश्चात सतत परिश्रम, लग्न एवं ईमानदारी से कार्य करते हुए अजमेर डेयरी को अत्यंत सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में ले आये हैं।

उन्होंने बताया कि अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा वर्ष 2019-20 में औसत लगभग 284 हजार किलो तथा वर्ष 2020-21 में 274 हजार किलो दूध प्रतिदिन खरीद कर वर्तमान में लगभग 2 लाख लीटर दूध का विपणन किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में 2032 एमटी घी तथा 1314 एमटी पाउडर तथा वर्ष 2020-21 में 2080 एमटी घी तथा 4088 एमटी पाउडर का उत्पादन किया जाकर उच्च गुणवत्ता के फलस्वरूप देश में सर्वाधिक भाव में विपणन किया गया, जिससे वर्ष भर दुग्ध उत्पादको को औसत 43.55 प्रति लीटर दूध भुगतान किया गया है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2019-20 में आयकर कटौती के पश्चात लगभग 3 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है, जिसमें से अनुमानतः 1.55 करोड़ रुपए बोनस एवं डिविडेन्ट शीघ्र ही पशुपालकों को कर दिया जायेगा। चौधरी ने बताया कि अजमेर डेयरी में 8 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का प्रोसेसिंग प्लांट (जिसकी विस्तार क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक है) एवं 30 एमटी प्रतिदिन क्षमता का नया पाउडर प्लांट दिसबर 2020 से प्रारभ किया जा चुका है। नवीन प्लांट में अन्य दुग्ध संघों से प्राप्त दूध का जॉब कार्य के तहत 52 मैट्रिक

▸▸ शेष @ 3 पर

सौभाग्यशाली है अजमेर डेयरी : विश्नोई

जोधपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष रामलाल विश्नोई ने अजमेर डेयरी की आमसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि अजमेर डेयरी बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें रामचन्द्र चौधरी जैसे समर्पित एवं निष्ठावान व्यक्तित्व का नेतृत्व मिला है, जिन्होंने डेयरी को विकास की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व खपा दिया है। अजमेर डेयरी तरक्की के लिए रात दिन एक कर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पशुधन और पशुपालकों के आर्थिक उन्नति में स्वयं को झोंक रखा है। विश्नोई ने कहा, मेरी भावना है कि रामचंद्र चौधरी राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा यदि डेयरी के माध्यम से पशुपालकों व किसानों के हित में सूत्रधार की अपनी भूमिका का निरंतर बनाये रखें।

चौधरी का नेतृत्व गौरव का प्रतीकः चेतन

इस मौके पर अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष चेतन चौधरी ने कहा कि अजमेर डेयरी की वार्षिक आमसभा में जिले के पशुपालकों और किसानों के लिए रामचन्द्र चौधरी का नेतृत्व बहुत ही गौरव का विषय है। वे पशुपालकों के मसीहा के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जिले के पशुपालकों और डेयरी सहकारिता के लिए हर राज्य सरकार से संघर्ष किया है, तब कहीं जाकर हम पशुपालन और डेयरी सहकारिता में प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर बने हुए हैं।

सम्पादकीय

कृषि कानूनों की वापसी

तीन कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा, तदोपरांत राज्यसभा व लोकसभा में कानून वापिसी के बिल पारित होने के राजनीतिक और आर्थिक मायने तलाशे जा रहे हैं। इन कानूनों को सितम्बर 2020 में संसद में पारित किया गया था। प्रधानमंत्री ने तीन विवादास्पद कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की तो ऐसी तमाम टिप्पणी सामने आईं जिनमें इस बात की व्याख्या की गई कि भारतीय कृषि के लिए ये निर्णय क्या मायने रखते हैं। आमतौर पर यही कहा गया कि नए कानूनों को वापस लेना कृषि सुधारों के लिए झटका है और सरकार को ऐसा तरीका निकालना चाहिए ताकि ऐसे महत्त्वपूर्ण निर्णय को बिना राजनीतिक विरोध के लागू किया जा सके।

ऐसी व्याख्याओं को गलत नहीं कहा जा सकता, हालांकि इनकी अपनी सीमा है। इनमें इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि भारतीय राजनीति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के वे कौन से बदलाव हैं, जिनके चलते मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। बीते कुछ वर्ष में देश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में कुछ नई ताकतें सामने आई हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इन वर्षों में देश में जड़ें जमा चुकी नई हकीकत की वजह क्या है? उस हकीकत के कई कारक हैं। उनका आकलन करके ही हम यह भी समझ पाएंगे कि कृषि कानूनों को कैसे और क्यों वापस लिया गया?

स्पष्ट बहुमत के दम पर मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढाते हुए जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और नागरिकता कानून में संशोधन करने में सरकार को बहुप्रतीक्षित सफलता मिली। सम्भवतः उस राजनीतिक सफलता ने मोदी सरकार को यह आत्मविश्वास दिया कि वह अपने आर्थिक एजेंडे पर भी उसी राजनीतिक बहुमत के सहारे आगे बढ़े। लेकिन यह सोच गलत था। राजनीतिक क्षेत्र में सही साबित हुए कदम आर्थिक क्षेत्र में कारगर नहीं रहे। यहां प्रस्तावित नीतिगत बदलाव से प्रभावित होने वाले अंशधारक अलग थे और उन्हें तगड़ा राजनीतिक सशक्तिकरण भी प्राप्त था। उत्तर भारत के किसानों और कुछ राज्य सरकारों पर दबाव बनाना आसान नहीं था।

किसानों के विरोध प्रदर्शन ने एक और बदलाव को जन्म दिया। विरोध प्रदर्शन करीब एक वर्ष तक चला और हाल के वर्षों में पहली बार यह स्थापित हुआ कि आंदोलन की राजनीति सरकार को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने का सही हथियार है। उत्तर भारत में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में यह व्यापक तौर पर देखने को मिला। आशा है कि आने वाले वर्षों में इससे ही राजनीति और आर्थिक नीति को स्वरूप मिलेगा।

आर्थिक नीति और राजनीति के बीच बदले हुए समीकरण का अर्थ यह भी है कि किसानों ने नए कृषि कानूनों का एक वर्ष लम्बा जो विरोध किया उसको ईंधन, किसानों के लिए प्रस्तावित नीतिगत ढांचे के विरोध से उतना नहीं मिला जितना कि इस राजनीतिक विचार से मिला कि केंद्र के सत्ताधारी दल के खिलाफ प्रतिपक्ष तैयार किया जाए। किसान आंदोलन की एक खासियत यह थी कि उसने ऐसे कई लोगों को एकजुट किया जो मोदी और उनकी राजनीति और नीतियों के खिलाफ थे। इसमें भी मोदी सरकार का विरोध मुखर था जबकि तीनों कृषि कानूनों के प्रावधानों का कम।

बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों का विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया देश की राजनीति में परिवर्तन बिंदु है। राजनीति अब यहां से कौन सी दिशा लेगी और क्या केंद्र राज्यों के साथ सहयोगात्मक भूमिका अपनाएगा, ये दोनों बातें भविष्य में आर्थिक नीति प्रतिष्ठान के स्वरूप को प्रभावित करने वाली होंगी।

राष्ट्र निर्माण में सहकारिताओं की अहम भूमिका : संघानी

आगामी पांच साल में पैक्स की संख्या में उल्लेखनीय बढोतरी होगी : त्रिपाठी

नई दिल्ली। कॉन्फिडरेशन ऑफ एनजीओ ऑफ रूरल इंडिया द्वारा गत दिवस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इरमा के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआइ) के अध्यक्ष दिलीप संघानी मुख्य अतिथ्य में 'को-ऑपरेटिव गवर्नेंस : भविष्य के अवसर' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में नेफेड के एमडी संजीव चड्ढा, वैम्निकोम निदेशक हेमा यादव, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के ओएसडी डॉ. के.के. त्रिपाठी, सीएनआरआई के अध्यक्ष मोहन कांडा (रिटायर्ड आईएएस) सहित सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अन्य प्रबुद्धजनों ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने सहकारिता क्षेत्र से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर जोर दिया। कई लोगों ने राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने की आवश्यकता की वकालत की, उनमें से कुछ ने पैक्स

को जीवंत और प्रभावी बनाने का सुझाव दिया।

अपने सम्बोधन में एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस सम्बंध में सहकारी समितियों का शीर्ष निकाय नई योजनाएं लेकर आ रहा है। संघानी ने कहा कि महिलाओं और छोटी सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'एनसीयूआई हाट' का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से छोटी संस्थाएं अपने उत्पाद को बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं ने कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्र की काफी मदद की है और उनमें से कई संस्थाओं ने पीएम केयर फंड और राज्य के सीएम राहत कोष में योगदान दिया था।

वैम्निकॉम के पूर्व निदेशक और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के ओएसडी डॉ. के.के. त्रिपाठी ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति और 97वें संविधान संशोधन पर जोर दिया, जिसे देश की शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि सहकारिता के सटीक डेटा को इकट्ठा करने की तत्काल आवश्यकता है। एनसीयूआई डेटा एकत्र कर रहा है लेकिन यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या एकत्र किया गया डेटा पर्याप्त है?

त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र सरकार पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के बारे में सोच रही है, साथ ही आगामी पांच साल में पैक्स की संख्या में वृद्धि करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत में 98 हजार प्राथमिक स्तर की समितियां हैं, जिनमें से केवल 64 हजार ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं। सदस्यता आधार बढ़ाने की आवश्यकता है और पैक्स को अन्य गतिविधियों में भी अपने व्यवसाय में विविधता लानी चाहिए।

उपभोक्ता मामले और समन्वय, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, आईआईपीए के चेयर प्रोफैसर सुरेश मिश्रा सहित अन्य वक्ताओं ने सहकारिता के लिए एक अलग केंद्रीय मंत्रालय बनाने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। डॉ आरबी सिंह, एफएनएएएस, अध्यक्ष सलाहकार बोर्ड ने डेयरी विकास के अमूल मॉडल के बारे में चर्चा की और सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता की वकालत की। सीएनआरआई, महासचिव, बिनोद आनंद ने कार्यक्र म का संचालन और समन्वयन किया।

राजस्थान में फसल बीमा पॉलिसी की संख्या एक करोड़ पार-कटारिया

कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को रवाना किया

जयपुर (सहकार गौरव)। कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार के नवाचारों, निरन्तर प्रचार-प्रसार एवं किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान करने से प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लोकप्रियता में निरन्तर वृद्धि हुई है। राज्य में वर्ष 2020-21 में फसल बीमा पॉलिसियों की संख्या एक करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। श्री कटारिया ने सोमवार को यहां अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को रवाना करते हुए बताया कि राज्य में वर्ष 2018-19 में लगभग 78 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल का फसल बीमा हुआ था, जो बढ़कर 20-21 में करीब 1 करोड़ 13 लाख हैक्टेयर हो गया है। फसल बीमा पॉलिसी की संख्या 2018-19 में 72 लाख से बढ़ते हुए 20-21 में 1 करोड़ 7 लाख हो गई है।

80 लाख किसानों को 13 हजार करोड़ का क्लेम : कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में पिछले 3 साल में 80 लाख से अधिक किसानों को लगभग 13 हजार करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के अलावा रबी 2020-21 तक के समस्त बीमा क्लेमों का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में गत सरकार के बकाया राज्यांश प्रीमियम के साथ-साथ रबी 2020-21 तक के लिए समस्त राज्यांश प्रीमियम का भुगतान बीमा कम्पनियों को कर दिया है। खरीफ 2021 के लिए राज्यांश प्रीमियम भुगतान प्रक्रियाधीन है।

25 दिसम्बर तक चलेगा प्रचार अभियान : कृषि आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 7 बीमा कम्पनी द्वारा फसल बीमा का काम किया जा रहा है। खरीफ में 19 तथा रबी में 17 फसलों का बीमा जिलों में बोई गई फसलों के हिसाब से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना का रबी के लिए 25 दिसम्बर तक व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काश्तकार अपनी फसलों का बीमा समय पर कराएं और यदि बोई गई फसल में कोई परिवर्तन किया है, तो सम्बंधित बैंक से सम्पर्क कर 29 दिसम्बर तक इसमें अवश्य परिवर्तन करा लें। इस अवसर पर कृषि विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. एसपी सिंह, विभागीय अधिकारी एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

'उद्यमिता विकास और सार्वजनिक निजी सहकारी भागीदारी को सुदृढ़ बनाना' विषय पर कार्यशाला का आयोजन

जयपुर (सहकार गौरव)। राजस्थान राज्य सहकारी संघ की ओर से गुरुवार को 68वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अन्तर्गत 'उद्यमिता विकास और सार्वजनिक निजी सहकारी भागीदारी को सुदृढ़ बनाना' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राइसेम निदेशक श्रीमती शिल्पी पांडे ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सीएल बुनकर, उप रजिस्ट्रार, जयपुर डेयरी यूनियन ने उद्यमिता विकास में सहकारिता की भूमिका पर प्रकाश डाला। किशोर सिंह, प्राचार्य, सहकारी प्रबंध संस्थान ने वर्तमान औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में सहकारिता के अन्तर्गत युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विचार व्यक्त किए। राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी आरएस चौहान ने उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया। राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी शंकर शरण शर्मा ने भारतीय संस्कृति में उद्यमिता विकास एवं सहकारिता के समन्वय पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन गजेन्द्र कुमार व्यास ने किया। भारती अग्रवाल, सरोज राठौड़ व ऋषि ने सहकार गीत गाया। प्रशिक्षणार्थी जोगाराम ने भी विचार व्यक्त किए।

नोखा और मालासर में लगेंगे बायोमॉस पॉवर प्लांट

जयपुर (सहकार गौरव)। राजस्थान में चूरू जिले के मालासर व बीकानेर जिले के नोखा में एक एक नए बायोमॉस पॉवर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने मंगलवार को राज्य ऊर्जा विकास निगम की वार्षिक साधारण सभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह में ही जयपुर के फागी व बीकानेर के छतरपुर में एक एक बायोमॉस पॉवर प्रोजेक्ट लगाने की स्वीकृति दी गई है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने और सस्ती दर पर विद्युत की उपलब्धता तय करने के लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अक्टूबर माह में आयोजित ऊर्जा विकास निगम की संचालक मंडल की बैठक में राज्य के चार विण्ड प्लांट से 2 रुपए 44 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद दर तय की जा चुकी है।

राजस्थान उर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक भास्कर ए सावंत ने बताया कि राज्य में बिजली के उत्पादन, उपलब्धता और मांग की लगातार मोनेटरिंग की जा रही है। देशव्यापी विपरीत परिस्थित के बावजूद राज्य में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने वर्तमान हालात से निपटने के लिए की जा रही कार्यवाही की विस्तार से जानकारी दी। वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षित लेखे व आगामी प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। साधारण सभा में वित्त सचिव टी. रविकांत, विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा, जयपुर डिस्कॉम के एमडी नवीन अरोड़ा, वित्त विभाग के प्रतिनिधि जेएस मेवाराम जाट, गोपाल विजय व सदस्यों ने हिस्सा लिया।

प्रशासन गांवों के संग अभियान : लम्बित प्रकरणों के लिए फॉलोअप कैम्प लगाने के निर्देश

जयपुर (सहकार गौरव)। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रशासन गांवों के संग अभियान से जुड़े विभागों को निर्देश दिये हैं कि वे शिविरों के दौरान त्वरित कार्यवाही कर आमजन के कार्यों का यथासंभव मौके पर ही निस्तारण करें। उन्होंने जिला कलक्टरों को भी अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे शिविर स्थल पर पेंडिंग रहे प्रकरणों को सूचीबद्ध करें। श्री आर्य ने विभागाधिकारियों को बताया कि बचे हुए प्रकरणों के निस्तारण के लिए जनवरी, 2022 में आवश्यकतानुसार फॉलोअप कैम्प आयोजित किये जाएंगे, जिनमें शेष रहे आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि शिविर में प्रस्तुत होने वाले हर एक आवेदन पर कार्यवाही की जाए और परिवादी को राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शिविरों के दौरान शेष रहे प्रकरणों की वे स्वयं मॉनिटरिंग करें। प्रकरणों की गांव के स्तर पर सूची बनाएं और इन प्रकरणों के शिविर में निस्तारण नहीं होने के कारणों का अंकन करवाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह तैयार सूचियों का जिला कलक्टर स्तर पर समुचित समीक्षा की जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे रिपोर्ट की समीक्षा कर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करवाएं।

पीएमसी बैंक के यूएसएफबी में विलय के मुद्दे पर आरबीआई ने सुझाव मांगे

मुम्बई। भारतीय रिजर्व बैंक पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी), जो कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कम्पनी है, में विलय पर विचार कर रहा है।

पीएमसी बैंक लिमिटेड को धोखाधड़ी, जिससे बैंक के निवल मूल्य में भारी गिरावट आई, के कारण आरबीआई ने 23 सितम्बर 2019 के निर्देशानुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35-ए की उप-धारा (1) के तहत सर्वसमावेशी निदेशों के तहत रखा गया था।

आरबीआई की ओर से जारी प्रेसनोट के अनुसार, निर्देश की अवधि को पिछली बार 25 जून 2021 के निदेश द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। पीएमसी बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए और पूंजी निवेश के प्रस्तावों के अभाव में, बैंक अपने आप में अर्थक्षम नहीं था। उस स्थिति में, कार्रवाई का एकमात्र तरीका इसके लाइसेंस को रद्द करना और इसका परिसमापन करना हो सकता था, जिसमें जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये की बीमा सीमा तक भुगतान प्राप्त होता। गत दिवस प्रकाशित समामेलन की मसौदा योजना में, जमाकर्ताओं के लिए अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना के प्रावधानों के संदर्भ में यूएसएफबी द्वारा जमाराशि सहित पीएमसी बैंक की आस्ति और देयताओं के अधिग्रहण को शामिल किया गया है। निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंक के ऑन-टैप लाइसेंसिंग के लिए 5 दिसम्बर 2019 के दिशानिर्देशों के तहत एक लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये की विनियामक आवश्यकता के विपरीत, समामेलन के बाद भविष्य की तारीख में और पूंजी डालने के प्रावधान के साथ लगभग 1,100 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ यूएसएफबी की स्थापना की जा रही है।

रिजर्व बैंक द्वारा ड्राफ्ट योजना पर सदस्यों, जमाकर्ताओं और हस्तांतरणकर्ता बैंक (पीएमसी) और हस्तांतरिती बैंक (यूएसएफबी) के अन्य लेनदारों से सुझाव और आपत्ति आमंत्रित की गयी हैं, जो कि 10 दिसम्बर 2021 को शाम 5 बजे तक प्राप्त की जाएगी। इसके बाद रिजर्व बैंक अंतिम विचार करेगा।

मार्च 2022 तक हर माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और चार महीने तक विस्तार देने को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण पांच) को और चार महीने, यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा।

इस योजना का पहला और दूसरा चरण क्रमशः अप्रैल से जून 2020 और जुलाई से नवम्बर, 2020 में परिचालन में था। योजना का तीसरा चरण मई से जून, 2021 तक परिचालन में रहा। योजना का चौथा चरण इस समय जुलाई-नवंबर, 2021 के दौरान चल रहा है। पीएजीकेएवाई योजना का पांचवां चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चलेगा, जिसमें अनुमानित रूप से 53344.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी दी जायेगी।

पीएमजीकेएवाई के पांचवें चरण के लिये खाद्यान्न का कुल उठान लगभग 163 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है।

उल्लेखनीय है कि 2020 में वर्ष देश में अप्रत्याशित रूप से कोविड-19 महामारी फैलने के कारण आने वाली आर्थिक अड़चनों को मद्देनजर रखते हुये, सरकार ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति, प्रति माह के हिसाब से पांच किलोग्राम अतिरिक्त रूप से निःशुल्क अनाज (चावल/गेहूं) दिया जायेगा, जो नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न, यानी उनके राशन कार्ड पर नियमित रूप से देय खाद्यान्न से अधिक होगा, ताकि गरीब, जरूरतमंद और जोखिम वाले घरों/लाभार्थियों को आर्थिक संकट के दौरान समुचित अनाज की अनुपलब्धता की वजह से वंचित न होना पड़े। अब तक पीएम-जीकेएवाई (एक से चार चरण तक) के तहत विभाग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल लगभग 600 लाख मीट्रिक टन का आवंटन किया है, जो लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर है।

खनिज लवणों से बढ़ सकती है पशुओं में वृद्धि, उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता

बीकानेर (सहकार गौरव)। वेटरनरी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य स्तरीय ई-पशुपालन चौपाल बुधवार को आयोजित की गई। पशु आहार में खनिज लवणों का महत्व विषय पर विशेषज्ञ डॉ. राजेश कुमार सावल ने पशुपालकों से वार्ता की। निदेशक प्रसार शिक्षा प्रो. राजेश कुमार धूड़िया ने विषय प्रवर्तन करते हुए बताया कि अधिकांश पशुपालक जागरूगता के अभाव के कारण पशुओं को संतुलित आहार एवं नियमित खनिज लवण नहीं खिलाते हैं जो कि पशुओं में वृद्धि दर में कमी के साथ-साथ उत्पादन में भी कमी का कारण बनता है एवं पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अतः खनिज लवण मिश्रण की पशु आहार में नितान्त आवश्यकता है। आमंत्रित विशेषज्ञ डॉ. राजेश कुमार सावल (प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर) ने बताया कि पशुओं में शारीरिक वृद्धि एवं दुग्ध, मांस, ऊन उत्पादन हेतु भोजन के आवश्यक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा खनिज लवणों की बहुत आवश्यकता रहती है। पशुपालक सामान्यतः पशुओं को संतुलित आहार नहीं खिलाते हैं, जिसके कारण पशुओं में खनिज लवणों की कमी से पशुओं में विभिन्न लक्षण जैसे शारीरिक वृद्धि में कमी, पाचन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, दुग्ध उत्पादन में कमी आदि मुख्य लक्षण दिखाई देते है।

उत्पादकता में वृद्धि के लिए खनिज लवण मिश्रण आवश्यक : उन्होंने बताया कि खनिज लवण मिश्रण को भारतीय मानक ब्यूरो के मापदण्डों के अनुसार विभिन्न खनिज लवणों को आवश्यकतानुसार निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। पशुपालकों को बड़े पशुओं जैसे गाय-भैस को 20-25 ग्राम प्रतिदिन एवं छोटे पशु जैसे भेड़ एवं बकरी को 5-10 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से बांटे या चारे में खिलाएं।

एनडीडीबी के हाथों में होगी पराग की बागडोर

वाराणसी। प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (पीसीडीएफ) द्वारा संचालित पराग डेयरी का संचालन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) को मिलने वाली है। इसका मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते डेयरी अपना पुराना वैभव खो चुकी है। डेयरी में पहले 25 सुपरवाइजर काम करते थे, अब पांच ही सुपरवाइजर के भरोसे ही काम चल रहा है। मंदी की मार झेल रहे डेयरी के दिन अब बहुरने वाले हैं। एनडीडीबी पांच साल तक पराग को चलाएगी और पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने का लक्ष्य रहेगा। एनडीडीबी भारत सरकार की एजेंसी है। देश में किसी भी पराग डेयरी में दिक्कत होने पर उसका समाधान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ही करती है।

PARAG
Ideas for a new day

बहुत जल्द ही पराग डेयरी की बागडोर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के हाथों में होगी। नई टीम पराग के व्यवसाय बढ़ने पर जोर देगी। 15 हजार लीटर प्रतिदिन के आवक को दो लाख तक पहुंचाकर पराग को पुराना रुतबा दिलाना चुनौतीपूर्व माना जा रहा है। एनडीडीबी को पांच साल तक के लिए पराग हस्तांतरित की मंजूरी मिल गई।

कर्मचारियों की कमी के कारण डेयरी घाटे में चली गई थी। अब अत्याधुनिक मशीनों के टेक्नीशियन की कमी दूर होगी। एनडीडीबी व शासन स्तर से हस्तांतरण के बाबत लिखा पढ़ी पूरी हो चुकी हैं। अब केवल स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण सम्बंधी कागजों का आदान प्रदान की कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की जायेंगी। शासन से मंजूरी का लेटर भी पराग को मिल चुका है। पराग डेयरी रामनगर के जीएम डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि शासन स्तर से पराग को एनडीडीबी को हस्तांतरित करने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। शासन के निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

एनडीडीबी के समक्ष कई चुनौती

पराग डेयरी के संचालन में एनडीडीबी को कई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पहले तो कर्मचारियों की संख्या बल को बढ़ाना होगा। इसके बाद तत्काल खाली पदों पर नियुक्ति करनी होगी। एनडीडीबी अपने अनुभवी कर्मियों को डेयरी में लगाकर इस कमी को पूरी करेगी। जबकि पराग में पहले से काम कर रहे कर्मियों का तबादला किया जाएगा। डेयरी से दूरी बना चुके मिल्क पार्लर व बूथ के साथ ही नये एजेंट जोड़ने होंगे और उनकी संख्या भी बढ़ानी होगी।

पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिए राज्य सरकार की 'बैक टू वर्क' योजना

जयपुर (सहकार गौरव)। शादी के बाद घर-परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है। नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 'बैक टू वर्क' योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।

इस योजना में आगामी 3 वर्ष में 15 हजार महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के क्रियान्वयन के लिए सहयोगी संस्था/सीएसआर संस्था के पोर्टल अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षित श्रेणी की महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड महिलाओं को श्रेणीवार डाटाबेस के आधार पर निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने का कार्य सीएसआर संस्था द्वारा किया जाएगा।

आवश्यकता होने पर सीएसआर संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड लक्षित श्रेणी की महिलाओं को री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग हेतु प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसका अपडेशन पोर्टल पर किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 'बैक टू वर्क' योजना शुरू करने की घोषणा की थी।

कृषि बजट पर फीडबैक के लिए बीकानेर सम्भाग की बैठक 3 दिसम्बर को

बीकानेर (सहकार गौरव)। राजस्थान में पहली बार पृथक से प्रस्तुत किये जाने वाले कृषि बजट पर फीडबैक लेने के लिए बीकानेर सम्भाग की बैठक 3 दिसम्बर को बीकानेर में होगी। इसमें सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग के समस्त जिलों के कलेक्टर, विभिन्न विभागों के सम्भाग व जिला स्तरीय अधिकारी, कृषि, कृषि विपणन, सहकारिता, कृषि विश्वविद्यालय और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

कृषि आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश की ओर से जारी पत्र के अनुसार, बैठक में प्रत्येक जिले से प्रगतिशील कृषक व पशुपालक, डेयरी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि उद्यमों के प्रतिनिधि, सिंचाई जल प्रबंधन इकाइयों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील मछलीपालक, कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि व सहकारी समितियों के प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे। इनसे कृषि बजट को लेकर सुझाव लिये जायेंगे, जिन्हें बजट पूर्व राज्यस्तरीय बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर को

श्रीगंगानगर (सहकार गौरव)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर श्रीगंगानगर जिले में 11 दिसम्बर 2021 आगामी द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, एडीजे पवन कुमार वर्मा ने बताया कि लोक अदालत सम्पूर्ण राष्ट्र में एक साथ एक ही दिन आयोजित की जा रही है, जिस किसी भी व्यक्ति को अपना प्रकरण चाहे वह न्यायालय में चल रहा हो या वह व्यक्ति अपना प्रकरण न्यायालय में दाखिल करवाने का विचार कर रहा हो, लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाना चाहता है, तो करवा सकता है। इसके लिए वह सम्बंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क कर सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाने के लिए पक्षकार ऑनलाइन व ऑफलाइन कोई भी माध्यम चुन सकता है।

लम्बित मामलों में आपराधिक मामले जो राजीनामा योग्य हैं तथा सिविल वाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण के मामले, बैंक, बीमा, बिजली विभाग से सम्बंधित मामले, दूरसंचार के मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम के मामले, भरण पोषण के मामले कई ऐसे ही अन्य मामले जो कानूनन राजीनामा योग्य हैं, उन्हें चिन्हित करवाया जा सकता है तथा कोई पक्षकार जिन मामलों को न्यायालय में पेश करने का विचार कर रहा है, उन्हें प्री-लिटिगेशन की स्टेज पर प्राधिकरण के समक्ष पेश कर सकता है।

श्री वर्मा ने बताया कि समस्त सूचीबद्ध प्रकरणों में प्री-काउन्सलिंग करवाने का प्रयास किया जावेगा, जिसमें दोनों पक्षों के बीच आपसी वार्ता करवाई जायेगी तथा उन्हें प्रकरण के राजीनामा होने के लाभ व नहीं होने के नुकसान के बारे में समझाइश की जायेगी।

श्रीगंगानगर जिले में सत्यनारायण व्यास, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता व मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय व सभी ब्लॉक में लोक अदालत आयोजित की जायेगी।

सहकारिता के मूल में सतत विकास के पहलू शामिल : आर्य

सिरोही (सहकार गौरव)। 68वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के उपलक्ष्य में जिला सहकारी संघ सिरोही की ओर से गांव नितोड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में सहकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पूर्व समिति परिसर में बुजुर्ग किसान नागाराम कलबी द्वारा सहकारिता ध्वज का ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रकाश आर्य ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि समिति के माध्यम से खेती के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराना, गांव में ही खाद, बीज, कीटनाशकों की उपलब्धता, समिति द्वारा उचित मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री का वितरण, समिति के मिनी बैंक में बचत जमा कराने व आवश्यक के समय निकालने की सुविधा, गांव में ही किसानों को बीमा सुविधा देना जैसे फसल बीमा, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि सहकारिता के मूल में सतत् विकास के पहलू शामिल हैं। सहकारिता नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है। सहयोग और सहकारिता के माध्यम से ही टिकाऊ समाज बनता है। सहकारिता गांव, ग्रामीण, किसान और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के उत्थान हेतु कृत संकल्प का वाचन किया गया।

गोष्ठी के दौरान उपस्थित समिति सदस्य कृषक नागाराम कलबी, भीखाराम घांची, गोपाराम कलबी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करने के पश्चात समिति अध्यक्ष लक्ष्मण लाल घांची ने किसानों का स्वागत किया। समिति व्यवस्थापक दुर्गेश कुमार ने समिति द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में गणेशाराम, सोमाराम, छगनलाल, देवाराम घांची, चमनलाल लखारा, दानाराम घांची, पूराराम कलबी, मेघाराम, सौदाराम, रणछोड़, गुलाब सिंह, भैराराम घांची, बालाराम घांची, शंकरलाल घांची, भोपालाराम पुरोहित, रामाराम सुथार, राजेंद्र सोलंकी, गौरव आर्य, लक्ष्मी देवी, पप्पूराम, सताराम रबारी, लुंबाराम घाची सहित ग्रामीण व किसान उपस्थित रहे।

कथाकार शिवमूर्ति को मिलेगा श्रीलाल शुक्ल इफको साहित्य सम्मान

नई दिल्ली। देश के प्रतिष्ठित श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान- 2021 के लिए हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति को चुना गया है। इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) की ओर से चयन समिति के निर्णय के साथ शिवमूर्ति के नाम की घोषणा की गई।

इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने कथाकार शिवमूर्ति को पुरस्कार के लिए बधाई दी है। राजकमल प्रकाशन समूह ने भी शिवमूर्ति को इफको साहित्य सम्मान के लिए बधाई दी है।

शिवमूर्ति ने कसाईबाड़ा, अकालदण्ड, तिरिया चरित्तर आदि कहानियों में उन्होंने महिलाओं, दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के संघर्षों को बड़े ही मार्मिक और सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में त्रिशूल, तर्पण, आखिरी छलांग और केसर कस्तूरी प्रमुख हैं। शिवमूर्ति की रचनाओं में सामंती व्यवस्था की विद्रुपता व कटु यथार्थ की प्रस्तुति रहती है। उन्होंने अपने कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन की विशेषताओं, विषमताओं और अंतर्विरोधों का यथार्थ चित्रण किया है।

श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान

श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में वर्ष 2011 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। यह सम्मान हर साल ऐसे हिन्दी लेखक को दिया जाता है, जिसकी रचनाओं में ग्रामीण और कृषि जीवन के लोग होते हैं। सम्मान स्वरूप कथाकार को 11 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न दिया जाता है। सम्मान समारोह हर वर्ष 31 जनवरी को होता है।

कथाकार शिवमूर्ति का परिचय

शिवमूर्ति का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक अत्यंत पिछड़े गांव कुरंग में हुआ था। 'कसाईबाड़ा', 'सिरी उपमा जोग', 'भरत नाट्यम', 'तिरिया चरित्तर' आदि उनकी प्रसिद्ध कहानी हैं। उनका कहानी संग्रह 'केशर कस्तूरी' काफी चर्चित रहा है। 'त्रिशूल' और 'तर्पण' उनके चर्चित उपन्यास हैं। 'कसाईबाड़ा' पर पांच हजार से अधिक बार मंचन हो चुका है और एक फीचर फिल्म भी बनी है। 'तिरिया चरित्तर' पर बासु चटर्जी ने फिल्म का निर्माण किया है।

शुगर मिल के नये पिराई सत्र के लिए 4 दिसम्बर तक करना होगा गन्ना अनुबंध

श्रीगंगानगर (सहकार गौरव)। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के गन्ना पिराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ना फाइनल सर्वे एवं गन्ना अनुबंध पत्र भरे जा रहे हैं।

शुगर मिल महाप्रबन्धक मुकेश बारेठ ने बताया कि जिन किसानों द्वारा अभी तक गन्ना अनुबंध पत्र नही भरे है, वे सम्बंधित गन्ना फील्ड सुपरवाइजर से सम्पर्क कर या गन्ना कार्यालय में आकर अपना अनुबंध पत्र 4 दिसम्बर 2021 तक भरवा सकते हैं। जो किसान 4 दिसम्बर 2021 तक अनुबंध पत्र नहीं भरेंगे, उसे गन्ना मांग पर्ची जारी करना सम्भव नही होगा। गन्ना अनुबंध करवाते समय किसान को अपना परिचय पत्र सुपरवाइजर को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा अनुबंध नही किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गन्ना पिराई सत्र 2021-22 में मोढी गन्ना की बॉण्ड 150 क्विंटल एवं बीजू गन्ना का बॉण्ड 200 क्विंटल से किया जाएगा। गन्ना मांग पर्ची की वैधता 5 दिवस की होगी।

प्रथम व अन्तिम पृष्ठ का शेष

सहकारिता सर्वस्पर्शीय और ...

की आवश्यकता के अनुसार कौन सा आर्थिक मॉडल उपयुक्त होगा, यह बहुत बड़ा विषय है।

महिला सशक्तिकरण का सफल प्रयोग है अमूल

उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण का सबसे सफल प्रयोग है। जो लोग महिला सशक्तिकरण के नाम पर एनजीओ चलाते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चला लीजिए तो आप महिलाओं का ज्यादा सशक्तिकरण कर पाएंगे और यह अमूल ने करके दिखाया है। (यह जानकारी पीआईबी की ओर से जारी प्रेसनोट में दी गयी।)

राजस्थान में अलग ...

अधिकारी व किसान अजमेर में राजस्थान शिक्षा बोर्ड के रीट सभागार में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए, किसानों का बजट पेश करने जा रही है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरूआत करने वाले कृषि बजट में उन्हीं प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाएगा, जो किसान चाहते हैं। इसी संदर्भ में सभी संभाग में किसानों, पशुपालकों, डेयरी संचालकों व मछली पालकों आदि से सम्वाद कर पूछा जा रहा है कि वे क्या चाहते हैं, कृषि बजट का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राज्य सरकार और किसानों में बेहतर समन्वय कैसे स्थापित हो, किसानों की क्या आवश्यकता हैं।

किसानों के सुझावों को सरकार के समक्ष रखेंगे : कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने कहा कि सम्भाग स्तरीय कृषक संवाद का यह पहला कार्यक्रम अजमेर से शुरू किया गया है। सम्वाद में किसानों द्वारा बताए गए मुद्दों को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा, साथ ही कार्यक्रम में प्राप्त सुझावों को उनकी प्राथमिकता व आवश्यकता के अनुसार राज्य बजट में शामिल किया जाएगा।

सुझावों पर विशेषज्ञों से चर्चा होगी : कृषि आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश ने कहा कि बैठक में प्राप्त सुझावों की लिस्टिंग करके विषय विशेषज्ञों से भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों की भी एक बैठक होगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपने सुझाव लिखित में भी जयपुर या अपने जिले में अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बैठक में सम्भागीय आयुक्त डॉ. वीना प्रधान, जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त गजेन्द्र सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे।

बीआर एक्ट में ...

रहा है, जो सहकारी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए निदेशक मंडल के साथ समानांतर कार्य करेगी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम का मतलब है कि सहकारी समितियां आरबीआई की अनुमति के बिना अपने उपनियमों में संशोधन नहीं कर सकती हैं।

मंत्रीमंडल में व्यापक ...

ऊपर से नीचे तक, बड़े परिवर्तन के कयास लगाये जा रहे थे, लेकिन आंजना का सहकारिता मंत्रायल का प्रभार यथावत रहने से विभाग को बड़े पैमाने पर होने वाली स्थानांतरण एवं पोस्टिंग के झंझावत से भी राहत मिल गयी है। अधिकारी अब पहले की भांति एकाग्रता एवं कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे।

सीनियर एडिशनल बलाई ...

रजिस्ट्रार-द्वितीय के पद पर कार्यरत हैं। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार जी.एल. स्वामी की 30 नवम्बर को सेवानिवृत्ति के पश्चात, राज्य सरकार ने दुर्गालाल बलाई को अतिरिक्त रजिस्ट्रार-प्रथम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। रजिस्ट्रार, सहकारी समियितां राजस्थान जयपुर कार्यालय में रजिस्ट्रार के बाद अब बलाई ही सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावीशाली अधिकारी हैं। रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली पत्रावली एडिशनल वन या एडिशनल टू के माध्यम से ही जाती हैं और चूंकि फिलहाल एडिशनल वन और टू, दोनों का प्रभार ही अब दुर्गालाल बलाई के पास है, इसलिए अब प्रत्येक पत्रावली उन्हीं की टिप्पणी के पश्चात रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बलाई 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त होंगे, उम्मीद की जा रही है कि तब तक, दोनों एडिशनल्स का कार्यभार उन्हीं के पास रहेगा।

एमडी ने सीयूजी ...

उठाने के मामले में दोषी माना गया है। झारोटिया वर्ष 2006 में उदयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में एमडी रहते हुए एसीबी द्वारा रंगे हाथों ट्रेप किये गये थे। उनके विरुद्ध एफआईआर 300/2006 एसीबी में पंजीबद्ध है और यह प्रकरण चालान संख्या 33/2008 में उदयपुर स्थित एसीबी की विशेष अदालत में विचाराधीन है। अजमेर सीसीबी में बजरंग लाल की यह पांचवीं पोस्टिंग है। पहले चारों बार उन्हें एपीओ किया गया था।

मोबाइल भत्ता के साथ डोंगल के लिए अलग से भुगतान उठाया : झारोटिया पर आरोप है कि उनके द्वारा जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक 67500 रुपये का भुगतान बैंक से बिना किसी वाउचर के मोबाइल, इंटरनेट सुविधा के नाम पर उठाया गया। मोबाइल सुविधा के नाम पर दो बार 10-10 हजार रुपये प्रति माह, सात बार 5-5 हजार रुपये प्रतिमाह तथा पांच बार 2500-2500 रुपये प्रतिमाह बैंक से प्राप्त किये गये। इसके पश्चात, मोबाइल, इंटरनेट के लिए सितम्बर 2019 से दिसम्बर 2020 तक, कुल 14 माह में 80 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त किया गया। इसके लिए दिसम्बर 2019 व जनवरी 2020 में उन्होंने प्रतिमाह 10-10 हजार रुपये तथा शेष 12 महीने प्रति माह 5000 रुपये का भत्ता बैंक से प्राप्त किया।

यानी जिस समय 199 रुपये के मासिक चार्ज में असीमित डाटा व कॉलिंग की सुविधा मोबाइल कम्पनी प्रदान कर रही थी, उस समय में झारोटिया ने बैंक से मोबाइल व इंटरनेट के नाम पर 28 माह में बैंक से 1 लाख 47 हजार 500 रुपये का भुगतान गैरकानूनी रूप से उठा लिया। इसके अलावा, इसी अवधि में कुल चार बार में, डोंगल व मोबाइल रिचार्ज के नाम पर 1641 रुपये का अलग से भुगतान प्राप्त किया। दिलचस्प तथ्य यह कि उपरोक्त अवधि में बैंक में प्रबंध निदेशक पद पर कार्य करते हुए बजरंग लाल झारोटिया ने अपने दो मोबाइल फोन सिम का सीयूजी प्लान के तहत उपयोग किया, जिसके बिल का भुगतान बैंक द्वारा किया गया।

शिकायत हुई तो 75000 रुपये जमा करवाये : सीयूजी प्लान के बावजूद, नियमविरुद्ध मोबाइल, इंटरनेट भत्ता उठाने का मामला प्रकाश में आने के बाद, बजरंग लाल झारोटिया ने बैंक के खाते में 75 हजार रुपये जमा करवा दिये, लेकिन शेष राशि पर मौन साध गये। हालांकि यह राशि चुकाने के लिए भी झारोटिया को बैंक अथवा जांच अधिकारी से किसी प्रकार का डिमांड नोटिस नहीं मिला था। जिस समय यह रकम जमा करायी गयी, तब झारोटिया एपीओ थे और बैंक प्रबंधन की नॉलेज में लाये बिना ही उन्होंने मेन ब्रांच में संधारित प्रधान कार्यालय के खाते में 75 हजार रुपये जमा करवा दिये।

पैक्स कर्मचारी संघ ...

सर्वाधिक सक्रिय सहकारी नेता हैं। उधर, संघ के भरतपुर सम्भाग के उपाध्यक्ष देवेंद्र सैदावत को पेक्स कर्मचारी संघ भारत का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सैदावत संघ की अलवर इकाई के जिलाध्यक्ष भी हैं। ये दोनों नियुक्तियां पैक्स कर्मचारी संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मिश्रा द्वारा की गई हैं।

डॉ. चंद्रपाल सिंह ...

अराय को केवल 83 वोट मिले। यादव ने 102 से अधिक मतों से जीत हासिल की, जो अंतरराष्ट्रीय सहकारी राजनीति में बड़ी बात है। यादव ने समर्थन देने के लिए एशिया-पैसिफिक क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं और देशों का धन्यवाद किया। भविष्य की रणनीति का साझा करते हुए उन्होंने कहा, मैं सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक और स्वायत्त चरित्र को बनाए रखने का प्रयास करूंगा। मैं सहकारी समितियों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच समन्वय बनाने का भी प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा, टीम के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, जो कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

जिले से अंतरराष्ट्रीय सहकारी राजनीति का सफर

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से सहकारी राजनीति की शुरूआत करने वाले चंद्रपाल यादव ने राज्य स्तर की सहकारी समितियों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपी सहकारी समितियों से वे कृभको बोर्ड में आए और बाद में शीर्ष संस्था एनसीयूआई के अध्यक्ष बने। वे एनसीयूआई के दो कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने। वे नेफेड, भारतीय सहकारी बैंक (कोबी) समेत कई राज्य और जिला स्तर के सहकारी संगठनों के बोर्ड में है। सहकारी समितियों के प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण में यादव का उल्लेखनीय योगदान रहा है।

राज्यसभा, लोकसभी सांसद रहे हैं यादव

19 मार्च 1959 को भारत के जालौन जिले के डाकोर गांव में स्वतंत्रता सेनानी और किसान परिवार में जन्मे चंद्रपाल सिंह यादव एम.एससी, बी.एड, एलएलबी शिक्षित हैं। यादव राज्यसभा और लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं और कई बार संसद में सहकारी समितियों से जुड़े मुद्दों को उठाया है। वह उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के सदस्य भी रहे। डॉ. यादव ने देश-विदेश में सहकारिता से जुड़े विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, बैठकों, कार्यक्रमों में भाग लिया है।

अजमेर डेयरी की ...

टन घी एवं 2234 मैट्रिक टन पाउडर का उत्पादन कर, 6.25 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि कोरोना की वजह से वर्ष 2019- 20 और वर्ष 2020-21 में वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं हो सका, इसलिए इस बार दोनों वर्ष के प्रस्ताव और लेखा-जोखा को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। चौधरी ने बताया कि 900 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 माह में 700 रुपये प्रति किलो फैट की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 50 दिन तक 650 रुपये और शेष दिन के लिए 660 रुपये प्रति किलो फैट की दर से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुग्ध खरीद के मूल्य में बढोतरी का भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जायेगा, इसलिए संघ के दुग्ध के विक्रय मूल्य में कोई बढोतरी नहीं करेगा। श्री चौधरी ने बताया कि अत्यधुनिक प्लांट में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही मुनाफा भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पशुपालकों को आश्वस्त किया कि 15 जनवरी 2022 तक समस्त बकाया भुगतान कर दिया जायेगा। अजमेर डेयरी के प्रबंध निदेशक उमेश चंद्र व्यास ने बताया कि आम सभा में दुग्ध उत्पादकों को 2 साल का बोनस देने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिला दुग्ध संघों को 6 माह की अनुदान राशि 9 करोड़ 45 लाख रुपए जारी की गई है। डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में दुग्ध उत्पादकों और उत्पादक संघों की प्रगति के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। आमसभा के बाद 2 बजे से खुला अधिवेशन हुआ, तत्पश्चात भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

जालोर सीसीबी की ...

दर में कमी करने सहित विभिन्न बिन्दु के सम्बंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने की बात कही गई। इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक के.के. मीणा ने सोसाइटी अध्यक्षों को अवगत करवाया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान अधिक से अधिक नये सदस्य बनाये जावें। जिन समिति के पास भण्डारण के लिए गोदाम नहीं हैं, वे समितियां गोदाम निर्माण के लिए प्रस्ताव भिजवायें। जिन सदस्यों की ऋण माफी हो गई है, उन कृषक सदस्यों को पुनः ऋण वितरण एवं किसान सम्मान निधि के जिन पात्र सदस्यों को लाभ नहीं मिल रहा है। उनको लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जावें।

खाद के लिए केंद्र सरकार को लिखेंगे

बैठक के अंत में प्रशासक नम्रता वृष्णि ने प्रस्तुत सभी विषयों पर शीघ्र कार्यवाही करने की बात कहते हुए कहा कि डीएपी खाद के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार को आग्रह किया जायेगा और नाबार्ड की ओर से देय सुविधाओं का लाभ प्रत्येक समिति को दिया जायेगा।

सहकारिता मंत्री की ...

गये हैं, इसलिए तकनीकी आधार पर वो धारा 107 में मंत्री की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत कर, किसी प्रकार का अनुतोष लेने का अधिकारी नहीं है, इसलिए तकनीकी आधार पर निगरानी को खारिज किया जाये। सहकारिता मंत्री ने बैंक के वकील जेपी महेंद्रा के तर्क को उपयुक्त मानते हुए निगरानी को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि वो अपनी अपील धारा 104 में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करें।

न जवाब दिया, न पेश हुआ : गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों द्वारा तत्कालिन प्रबंध निदेशक मंगतराम पर बैंक की वार्षिक आमसभा में लगाये गये गम्भीर आरोपों के पश्चात, खन्ना के विरुद्ध विभागीय जांच एवं तत्पश्चात अधिनियम अंतर्गत जांच करवायी गयी थी। इस दौरान मंगतराम को दर्जनबार से अधिक नोटिस जारी किये गये, लेकिन वह न तो स्वयं प्रस्तुत हुआ, न ही कोई जवाब दिया। यह सिलसिला धारा 57 में प्रकरण दर्ज होने के पश्चात से आज तक चल रहा है। धारा 57 की सुनवाई के लिए खंडीय कार्यालय द्वारा मंगतराम को 8 बार नोटिस दिया गया, जिनमें से 4 बार नोटिस तामिल होने के बावजूद वह किसी पेशी पर नहीं पहुंचा, न ही लिखित में कोई जवाब दिया।

उदयलाल आंजना का ...

आंदोलन में, विशेषकर सहकारी बैंकों में जवाबदेह, जिम्मेदार, पारदर्शी एवं कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था पर और अधिक प्राथमिकता केंद्रित कर कार्य संस्कृति में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने किसानों के लिए लाभकारी बीमा योजनाओं में सुधार कर लागू करना, सहकारी बैंकों में ऋण विविधिकरण के तहत विभिन्न ऋण योजनाओं को शुरू करवाना समय क आवश्यकता है। आमेरा ने इसके साथ ही पैक्स का कम्प्यूटरीकरण कर बैंक सीबीएस से जोड़ने, सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती करने, पैक्स में कार्मिकों के नियोक्ता निर्धारण के लिए कैडर लागू करने, पैक्स/लेम्प्स में व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग कर हजारों की रिक्त पदों पर भर्ती करने, किसानों को कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी, मत्यस्य गतिविधियों के लिए ऋण वितरण करने, महिला स्वयं सहायता समूह व किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) गठन पर जोर देने, सभी सहकारी संस्थाओं व सहकारी बैंकों में आंतरिक नियंत्रण, निरीक्षण व ऑडिट की प्रभावी विजिलेंस व्यवस्था लागू करने और समस्त सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाकर लोकतांत्रिक स्वरूप बहाल करने की भी जरूरत बतायी।

मिट्टी में रसायन ...

मिलीलीटर नैनो यूरिया की एक बोतल पर्याप्त होगी। इस दौरे के दौरान अवस्थी ने नवनिर्मित जनसम्पर्क कार्यालय और ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। साथ ही, फूलपुर इकाई में नवनिर्मित सेफ्टी कम सेफ्टी इंस्ट्राक्शन रूम का भी शुभारम्भ किया। इससे पहले उन्होंने कलोल और आंवला प्लांट का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था।

कलेक्टर ने किया ...

सहायता समूहों को ऋण वितरण किया जा चुका है। समिति में ग्रेडिंग एवं सोर्टिंग प्लान्ट और रूरल मार्ट मोबाईल वैन के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

इस अवसर पर सरपंच श्रीमती हेमन्त कंवर, हरिसिंह सोलंकी, सहायक व्यवस्थापक प्रकाश सिंह व नरपतसिंह, सलाहकार प्रागाराम, शांतिलाल भट्ट, पदमाराम, गंगाराम, महेन्द्रसिंह चौहान एवं हकाराम भाटी आदि उपस्थित थे।

7 जिलों में ...

अलायला	भादरा
सरावांवाला	पीलीबंगा
निरवाल	रावतसर
राठीखेड़ा	टिब्बी
जिला कोटा	
मदनपुरा	खैराबाद
देवलीकलां	खैराबाद
मण्डा	खैराबाद
लोढाहेड़ा	सांगोद

सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार ...

सीसीबी बीकानेर, सीसीबी नागौर, उप रजिस्ट्रार बीकानेर और सहकारी भंडार बीकानेर में महाप्रबंधक के रूप में सेवा दी।

2012 में हुआ प्रधान कार्यालय में पदस्थापन

वर्ष 2012 में समग्र सहकारी विकास परियोजना में पोस्टिंग के बाद से श्री स्वामी सहकारिता मुख्यालय में नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं। इस दौरान वे एडिशनल मार्केटिंग, एडिशनल-टू और एडिशनल वन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए सहकारिता विभाग से जी.एल. स्वामी का नाम दो बार भेजा गया।

सर्वश्रेष्ठ उप रजिस्ट्रार चुने गये, मंत्री ने सम्मानित किया : श्री स्वामी को रायसिंहनगर व हनुमानगढ़ पीएलडीबी में सचिव पद पर कार्य करते हुए राज्य में सर्वाधिक ऋण वसूली के लिए तीन बार श्रेष्ठ सचिव का पुरस्कार मिला। वर्ष 2008 में राज्य के सर्वश्रेष्ठ उप रजिस्ट्रार चुने गये, तब उन्हें तत्कालीन सहकारिता मंत्री नाथूलाल गुर्जर और रजिस्ट्रार सुधांशु पंत की ओर से सम्मानित किया गया था।

जालोर सीसीबी की आमसभा, बैंक को हुआ 2.98 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ

जालोर (सहकार गौरव)। दी जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालोर की 61वीं वार्षिक आमसभा जिला परिषद के भारत निर्माण सेवा केन्द्र में बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से सम्पन्न हुई। आमसभा में बैंक के हिस्साधारी सहकारी समितियों एवं अन्य समितियों के अध्यक्षों ने भाग लिया।

प्रशासकीय उद्बोधन में जिला कलटर नम्रता वृष्णि ने बैंक के वर्ष 2020-21 की अवधि के लेखे प्रस्तुत करते हुए बताया कि बैंक की हिस्सा पूंजी 3708.80 लाख रुपये एवं बैंक की अमानतें बढ़कर 49211.01 लाख रुपये रही है। बैंक की कार्यशील पूंजी 93901.15 लाख रुपये हुई है। वित्तीय वर्ष के अन्त में बैंक का सकल लाभ 1197.05 लाख रुपये में से 891.67 लाख रुपये का प्रावधान करने के पश्चात 2 करोड़ 98 लाख 38 हजार रुपये का शुद्ध लाभ रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सहकारी विभाग की सभी प्रचलित योजनाओं में सहभागी रहकर आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर सभी प्रकार की वित्तीय सुविधा सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से समग्र रूप से उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी हैं।

बैंक के प्रबन्ध निदेशक के. के. मीणा द्वारा बैंक की गत वार्षिक साधारण सभा का कार्यवाही विवरण की पुष्टि प्राप्त करने के साथ ही वर्ष 2020-21 के 61वें वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेखित बैंक कार्य की पुष्टि सदन से प्राप्त की गई। साथ ही, वार्षिक लेखों का अनुमोदन, बजट का निर्धारण, वार्षिक कार्य योजना, बैंक की अधिकतम साख सीमा का निर्धारण किये जाने का अनुमोदन भी सदन से प्राप्त किया गया। बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के शेष लाभ में से 2 प्रतिशत लाभांश को हिस्सा पूंजी के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव भी अनुमोदन करवाया गया।

अध्यक्षों ने एलएस भर्ती, स्क्रीनिंग का मुद्दा उठाया : आमसभा में बैंक में रिक्त ऋण पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती, व्यवस्थापकों व सहायक व्यवस्थापकों के स्क्रीनिंग एवं सहकार किसान कल्याण ऋण योजनान्तर्गत ब्याज ▸▸ शेष @ 3 पर

सोसाइटी अध्यक्षों ने दिये सुझाव

इस अवसर पर प्रतापपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष मनोज कुमार विश्नोई ने रबी ऋण वितरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर ऋण वितरण किये जाने का सुझाव दिया। उन्होंने डीएपी खाद और समिति को कोल्ड स्टोरेज के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने की बात कही। कारोला समिति अध्यक्ष पीराराम देवासी द्वारा पोर्टल पर अपलोड 5 ऋण पत्रावली की एमसीएल स्वीकृति की बात रखी। सिराणा समिति अध्यक्ष किशन सिंह ने बीमित फसलों के सर्वे के दौरान समिति अध्यक्ष को सम्मिलित करने का सुझाव दिया। पुनककलां समिति सदस्य वाघसिंह ने खाद की कमी के कारण काश्तकारों की समस्या को देखते हुए अल्पकालीन ऋण वितरण में बढ़ोतरी करने का आग्रह किया। बावडी समिति अध्यक्ष राजवीरसिंह देवड़ा ने ग्राहकों की सुविधा के लिए आहोर पंचायत समिति में दो नई शाखा भाद्राजून एवं चांदराई में खोलने का सुझाव दिया। बैंक के पूर्व संचालक ने नोसरा ग्राम में भी शाखा खोलने के लिए सर्वे करवाने तथा सभी समितियों को प्रिन्टर उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। प्रबंध निदेशक ने समिति अध्यक्षों के सुझावों पर यथोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

सहकारिता मंत्री की कोर्ट ने खारिज की मंगतराम की निगरानी

जयपुर (सहकार गौरव)। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी और जेल की हवा खाने के बाद निलम्बित चल रहे सहकारिता सेवा के अधिकारी मंगतराम खन्ना की आशाओं पर आज कठोर वज्रपात हुआ, जब सहकारिता मंत्री की कोर्ट ने मंगतराम को झटका देते हुए 61 लाख 38 हजार 907 रुपये की वसूली के विरुद्ध दायर रिवीजन (निगरानी) को खारिज कर दिया।

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की छठी मंजिल पर बुधवार को आयोजित सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की कोर्ट ने मंगतराम के वकील के तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए निगरानी (याचिका) को निरस्त कर दिया। मंगतराम द्वारा गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लि. में प्रबंध निदेशक रहते हुए जो वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं की गयी थी, उसकी राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 की जांच में पुष्टि के पश्चात तत्कालीन बीकानेर खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार रविंद्र कुमार पुरोहित द्वारा खन्ना के खिलाफ धारा 57 में प्रकरण में पजीबद्ध करते हुए, वसूली की कार्यवाही आरम्भ की गयी थी।

मंत्री की कोर्ट में मंगतराम के वकील ने खन्ना को सुनवाई का उचित अवसर नहीं देने का तर्क देते हुए धारा 55 के जांच परिणाम को रद्द करने और प्रकरण समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन बैंक के वकील ने धारा 55 के जांच अधिकारी द्वारा खन्ना को जारी एवं तामिल नोटिस तथा बीकानेर खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार की अदालत द्वारा जारी एवं तामिल नोटिस की प्रति प्रस्तुत की, साथ ही सितम्बर 2021 में मंगतराम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही की तथ्यात्मक एवं एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर में सम्मिलित अत्यंत गम्भीर आरोपों की बिन्दुवार जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी।

रजिस्ट्रार के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का निर्देश : बैंक के वकील ने अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए कोर्ट को बताया कि चूंकि, मंगतराम के विरुद्ध धारा 55 के जांच परिणाम खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार बीकानेर द्वारा जारी किये ▸▸ शेष @ 3 पर

उदयलाल आंजना का सहकारिता मंत्री प्रभार यथावत रखने पर सहकार नेता आमेरा ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

जयपुर (सहकार गौरव)। ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्पलॉइज यूनियन व ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रान्तीय महासचिव तथा सहकारी साख समितियां एम्पलॉइज यूनियन राजस्थान के प्रान्तीय अध्यक्ष सूरज भान सिंह आमेरा ने गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन में उदयलाल आंजना का सहकारिता मंत्री के रूप में प्रभार यथावत रखने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देते हुए राज्य के पैक्स से अपेक्स तक के कार्मिको की तरफ से आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे सहकारी आंदोलन के हित में सही निर्णय बताते हुए कहा कि सरकार में कार्य कुशलता, नीतियों व निर्णयों को देखते हुए चुनिंदा पूर्व मंत्रियों का ही प्रभार यथावत रखा गया है जिसमें सहकारिता मंत्रालय भी एक है।

सहकार नेता आमेरा ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे किसानों, सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों व समग्र आंदोलन की कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों में निरंतरता से गति मिलेगी। आमेरा ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकार के एजेंडे को साकार करने के लिए सहकारी साख ▸▸ शेष @ 3 पर

मिट्टी में रसायन की समस्या से निजात दिलायेगा इफको का नैनो लिक्विड यूरिया : अवस्थी

फूलपुर (सहकार गौरव)। इफको के प्रबंध निदेशक डॉ यू.एस.अवस्थी ने हाल ही में प्रयागराज स्थित संस्था की फूलपुर इकाई का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की।

कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए, अवस्थी ने मिट्टी में रसायन के कम प्रयोग के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि इस समस्या से निजात पाने में इफको नैनो यूरिया काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इफको की फूलपुर इकाई में नैनो संयंत्र का संचालन नवम्बर 2022 तक आरम्भ कर दिया जाएगा।

अवस्थी ने बताया कि इफको की फूलपुर इकाई प्रतिदिन दो लाख नैनो यूरिया बोतलों का उत्पादन करेगी। एक एकड़ जमीन के लिए 500 ▸▸ शेष @ 3 पर

कलेक्टर ने किया सियाणा समिति का निरीक्षण, सोसाइटी के कार्यों को सराहा

जालोर (सहकार गौरव)। जिला कलक्टर और जालोर केंद्रीय सहाकरी बैंक की प्रशासक नम्रता वृष्णि ने ग्राम सेवा सहकारी समिति सियाणा में संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों, मिनी बैंक तथा सियाणा समिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने समूहों द्वारा निर्मित सामेला के बेड़े, तौरण, ईडाणी, मॉस्क एवं अन्य उत्पादित सामग्री का अवलोकन कर समूहों के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए समूहों को अन्य उच्च स्तरीय सामग्री, ब्यूटी पार्लर एवं अगरबत्ती उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों को शून्य प्रतिशत के.सी.सी. ऋण का वितरण भी किया। सीसीबी के प्रबंध निदेशक ने जिला कलेक्टर

को बताया कि सियाणा मिनी सहकारी बैंक में 25 करोड़ रुपए की एफडीआर है। समिति में वर्तमान में लघु, मध्यम एवं दीर्घ साइज के 500 लॉकर्स उपलब्ध हैं। सियाणा समिति में 2270 सदस्य है। समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 2.50 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया। सियाणा समिति से 105 स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए है जिसमें से 35 स्वयं ▸▸ शेष @ 3 पर

7 जिलों में 25 और नई पैक्स व लैम्पस के गठन की स्वीकृति जारी

जयपुर (सहकार गौरव)। सहकारिता विभाग द्वारा राज्य के 7 जिलों में 25 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की गयी है। रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूची निम्न प्रकार से है -

नई समिति	पंचायत समिति
जिला झुंझुनूं	
झांझा	बुहाना
गोखरी	अलसीसर
हमीनपुर	पिलानी
जिला श्रीगंगानगर	
30 एपीडी	अनूपगढ़
जिला नागौर	
काशीनगर	मकराना

जिला बासंवाड़ा (लैम्पस)	
भचड़िया	तलवाड़ा
कुवालिया	अरथूना
निचली	मोरडी घाटोल
पडोली	राठौड़ घाटोल
सामरिया	बांसवाड़ा
नवागांव	सज्जनगढ़
जीवाखुंटा	सज्जनगढ़
जिला उदयपुर	
वल्लभनगर	भीण्डर
बरोड़िया	भीण्डर
गुडली लैम्प्स	बम्बोरा
घोड़ासर लैम्प्स	सराड़ा
जिला हनुमानगढ़	
राजपुरा	भादरा

▸▸ शेष @ 3 पर

राजस्थान के डेयरी किसान सुरेन्द्र अवाना राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित

कृत्रिम गर्भाधान श्रेणी में तकनीशियन राजेश बागड़ा को भी मिला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

जयपुर (सहकार गौरव)। स्वदेशी नस्लों से डेयरी व्यवसाय करने वाले राज्य के प्रगतिशील डेयरी किसान सुरेन्द्र अवाना और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन राजेश बागड़ा को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द (गुजरात) की ओर से शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में गाय-भैंसों की प्रमाणित स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन तथा सहकारी एवं दुग्ध उत्पादक कम्पनियों को केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत यह पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गोपाल रत्न पुरस्कार की 9 श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए। श्री रूपाला ने राजस्थान से स्वदेशी नस्लों की डेयरी किसान में प्रथम पुरस्कार के रूप में सुरेन्द्र आवाना को 5 लाख रुपए एवं सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन राजेश बागड़ा को तृतीय पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए देकर सम्मानित किया।

मंत्री व शासन सचिव ने दी बधाई : पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया एवं पशुपालन शासन सचिव डॉ. आरुषि मलिक ने सुरेंद्र अवाना एवं राजेश बागड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार मिलना हमारे प्रदेश और विभाग के लिए गर्व की बात है। इससे डेयरी किसानों और पशुपालन विभाग के कार्मिकों को ज्यादा कर्मठता से काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

राजावत के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री को शुभकामनायें दी

जयपुर। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की ओर से राज्य मंत्रिमंडल पुनर्गठन में उदयलाल आंजना का सहकारिता मंत्री का प्रभार यथावत रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सिंह राजावत के नेतृत्व में संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सहकारिता मंत्री से मुलाकात कर, संघ और प्रदेश के समस्त पैक्स, लैम्पस कर्मचारियों की ओर से शुभकामनाओं के रूप में गुलदस्ता भेंट किया गया। राजावत, प्रदेश महामंत्री नंदाराम चौधरी और अजमेर सम्भाग के उपाध्यक्ष हीराराम रूलानिया ने आंजना का सहकारिता मंत्रालय का प्रभार यथावत रखने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है।

सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार जी.एल. स्वामी सेवानिवृत्त

जयपुर (सहकार गौरव)। सहकारिता सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गिरधारीलाल स्वामी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर 30 नवम्बर 2021 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये। अतिरिक्त रजिस्ट्रार सीनियर स्केल के अधिकारी श्री स्वामी ने अपनी सेवानिवृत्ति पर किसी प्रकार के विदाई समारोह का आयोजन करने की सहमति नहीं दी। अन्तिम कार्यदिवस की संध्या को बेहद सादगीपूर्ण माहौल में वे अपने पुत्र के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय से रवाना

हो गये। सेवानिवृत्ति के दिन सहकारिता सेवा के अनेक अधिकारियों, कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर श्री स्वामी को जीवन की दूसरी पारी के लिए शुभकामनायें दी।

वे 34 वर्ष से अधिक की राजकीय सेवा में सहकारिता विभाग में महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर रहे और विभिन्न सहकारी संस्थाओं में मुख्य कार्यकारी के रूप में सराहनीय सेवा दी। श्री स्वामी 1985 बैच के अधिकारी हैं, हालांकि इस बैच को पहली पोस्टिंग 1 जुलाई 1987 को मिली। छह माह की जॉब ट्रेनिंग के पश्चात भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में कॅरियर की विधिवत शुरूआत हुई। एआर डेयरी से एडिशनल रजिस्ट्रार-वन के सफर के दौरान उन्होंने क्रय विक्रय सहकारी समिति गजसिंहपुर, डीआरडीए गंगानगर, पीएलडीबी हनुमानगढ़, पीएलडीबी रायसिंहनगर, स्पिनफैड हनुमानगढ़, पीएलडीबी सिरोही, सीसीबी टोंक, पीएलडीबी बीकानेर, ▸▸ शेष @ 3 पर

सहकारी कर्मचारी संघ : परमेश्वर वैष्णव अजमेर जिलाध्यक्ष निर्वाचित

अजमेर (सहकार गौरव)। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ अजमेर की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मती से भूपेंद्र सिंह नसीराबाद संरक्षक, परमेश्वर वैष्णव जिला अध्यक्ष, महावीर रेगर केकड़ी-उपाध्यक्ष, सुखपाल अजमेर-उपाध्यक्ष, ओमप्रकाश रेगर सरवाड़-उपाध्यक्ष, सतीश जांगिड़ केकड़ी-सचिव, सत्य नारायण शर्मा सरवाड़-कोषाध्यक्ष चुना गया।

जिला कार्यकारिणी में अल्लाह बख्श भिनाय, गोविन्द सिंह नसीराबाद, राहुल कुमार पुष्कर, लालाराम पीसांगन, अनिल कुमार किशनगढ़, रामकिशन अराई और नाथूलाल बिजयनगर को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

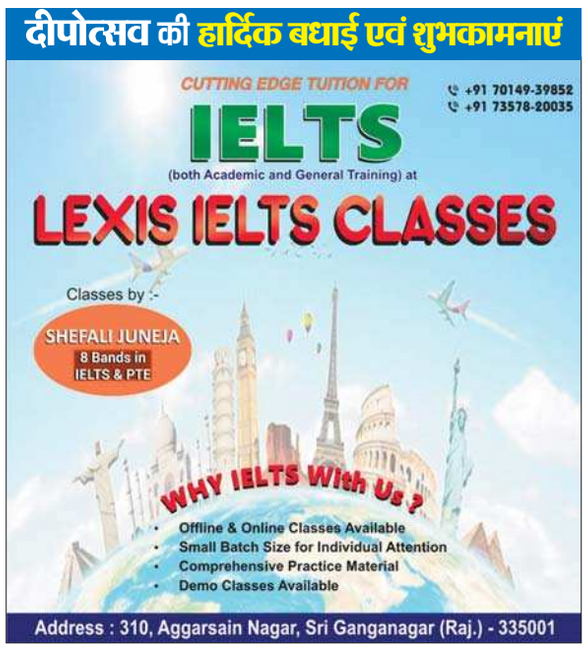

राजस्थान की पहली किसान ट्रेन में अलवर स्टेशन से बेहटा के लिए भेजा गया प्याज

जयपुर (सहकार गौरव)। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल पर अलवर स्टेशन से 1836 किलोमीटर दूर आसाम के बेहटा स्टेशन के लिए पहली बार किसान रेल योजना के अंतर्गत प्याज का लदान किया गया।

मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशिकिरण ने बताया कि महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे विजय शर्मा की पहल पर उत्तर पश्चिम रेलवे के पहली किसान रेल अलवर स्टेशन से आसाम के लिए रवाना की गई। इस किसान रेल के 22 डिब्बों में प्याज लदान किया गया जिसके लिए 5 लाख 611 रुपए किराया लिया गया। जबकि कुल वास्तविक किराया 9 लाख 81 हजार 967 था। किराये की शेष रकम 4 लाख 81 हजार 356 रुपए रेलवे ने सब्सिडी

के रूप में वहन किया है।

उन्होंने बताया कि रेलवे रोड परिवहन को रेलवे पर आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजना चलाई जा रही हैं, इसके अंतर्गत व्यापारी अपने माल को सस्ता, शीघ्र एवं सुगम तरीके से रेलवे द्वारा पहुंचा सकता है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक मनीष मुंजाल के आदेशानुसार न्यू भाटिया प्रिंटर्स, 125 गोल बाजार, श्रीगंगानगर से मुद्रित तथा 392 चांदनी चौक, रामनगर, श्रीगंगानगर से प्रकाशित। मो.: 9782056056 - सभी प्रकार के वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र श्रीगंगानगर होगा। RAJHIN/2013/57037